

स्वास्थ्य का अधिकार

प्रलिस के लयः

स्वास्थ्य का अधिकार, सातवीं अनुसूची, नजी वधियक, सार्वजनिक वधियक

मेन्स के लयः

अरथवयवस्था में स्वास्थ्य कषेतर का महत्त्व, समावेशी स्वास्थ्य प्राप्त करने में चुनौतयौं, सरकारी पहल

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में राज्यसभा में एक नजी सदस्य के वधियक “स्वास्थ्य का अधिकार वधियक” पर गहन चर्चा हुई ।

- इसका लक्ष्य सभी विकास नीतयौं में नवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल अभवनयास के माध्यम से सभी उमर के सभी लौगौं हेतु स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करना है ।
- वधियक सभी नागरिकों के लयि स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार बनाने और गरमिपूरण जीवन जीने हेतु अनुकूल शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के मानक के समान पहुँच तथा रखरखाव सुनश्चिति करने का प्रयास करता है ।

स्वास्थ्य का अधिकार:

परचयः

- अन्य अधिकारों की तरह स्वास्थ्य के अधिकार में भी स्वतंत्रता एवं पात्रता दोनों घटक शामिल हैं:
- स्वतंत्रता में स्वयं के स्वास्थ्य और शरीर को नयितरति करने का अधिकार (उदाहरण के लयि यौन एवं प्रजनन अधिकार) तथा हस्तकषेप से मुक्तता का अधिकार शामिल है (उदाहरण के लयि यातना एवं गैर-सहमता चिकित्सा उपचार और प्रयोग से मुक्तता) ।
- ‘पात्रता’ के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा की एक प्रणाली का अधिकार शामिल है, जो सभी को स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य स्तर का लाभ प्राप्त करने का अवसर देता है ।

भारत में संबंधित प्रावधानः

अंतर्राष्ट्रीय अभसिमयः

- भारत [संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा \(1948\)](#) के अनुच्छेद-25 का हस्ताकषरकर्त्ता है जो भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और अन्य आवश्यक सामाजिक सेवाओं के माध्यम से मनुष्यों को स्वास्थ्य कल्याण के लयि पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार देता है ।

मूल अधिकारः

- भारत के संवधान का [अनुच्छेद-21](#) जीवन और व्यक्तगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है ।
- स्वास्थ्य का अधिकार गरमियुक्त जीवन के अधिकार में नहिति है ।

राज्य नीति के नदिशक तत्त्व (DPSP):

- [अनुच्छेद 38, 39, 42, 43 और 47](#) ने स्वास्थ्य के अधिकार की प्रभावी प्राप्ति सुनश्चिति करने के लयि राज्यों का मार्गदर्शन कया है ।

न्यायिक उद्घोषणाः

- पश्चिम बंगाल खेत मज़दूर समतिमामले (1996) में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का प्राथमिक कर्तव्य लौगों का कल्याण सुनश्चिति करना और उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुवधि प्रदान करना है ।
- परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले (1989) में अपने ऐतहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हर डॉक्टर चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो या फरि अन्य कहीं, जीवन की रक्षा के लयि उचित वशिषज्ज्ञता के साथ अपनी सेवाएँ देना उसका पेशेवर दायित्व है ।

महत्त्वः

स्वास्थ्य सेवा आधारित अधिकारः

- लौग स्वास्थ्य के अधिकार के हकदार हैं और सरकार द्वारा इस दशि में कदम उठाना उसका उत्तरदायित्व है ।

- **स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक पहुँच:**
 - यह सभी को सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है और सुनिश्चित करता है कि सेवाओं की गुणवत्ता उन लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिये पर्याप्त है।
- **व्यय को कम करना:**
 - लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय करने के वित्तीय परिणामों से बचाता है और उन्हें गरीबी में धकेलने जैसे जोखिम को कम करता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियाँ:

- **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में कमी:**
 - देश में मौजूदा सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का दायरा सीमित है।
 - यहाँ तक कि एक अच्छी तरह से कार्यरत सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी केवल गर्भावस्था देखभाल, सीमिति चाइल्ड केयर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित कुछ सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- **अपर्याप्त धन:**
 - भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य नधिपर व्यय लगातार कम रहा है (सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.3%)।
 - OECD के अनुसार, भारत का कुल 'आउट-ऑफ-पॉकेट' खर्च जीडीपी का लगभग 2.3% है।
- **उप-इष्टतम सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली:**
 - स्वास्थ्य प्रणाली में त्रुटियों के कारण **गैर-संचारी रोगों** से नपिटना चुनौतीपूर्ण है, जो कि रोकथाम और रोगों का शीघ्र पता लगाने से संबंधित है।
 - यह कोवडि-19 महामारी जैसे नए एवं उभरते खतरों की तैयारियों में कमी और इनके प्रभावी प्रबंधन को कमजोर करता है।

आगे की राह

- **अधिक धन आवंटित करना:**
 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में की गई परकिल्पना के अनुसार, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक वित्त को जीडीपी के कम-से-कम 2.5% तक बढ़ाया जाना चाहिये।
 - इस संबंध में स्वास्थ्य के अधिकार को शामिल करने वाला एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून संसद द्वारा पारित किया जा सकता है।
- **नोडल स्वास्थ्य एजेंसी का निर्माण:**
 - रोग की नगिरानी के लिये नामति और स्वायत्त एजेंसी बनाने की आवश्यकता है, जो प्रमुख गैर-स्वास्थ्य संबंधी वभिगों की नीतियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव की जानकारी एकत्र करे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य ऑकड़ों का रखरखाव करे ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य नयिमों का प्रवर्तन और इससे संबंधित सूचनाओं का प्रसार जनता तक हो।
- **अन्य उपाय:**
 - स्वास्थ्य को संवधान के तहत सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिये। वर्तमान में 'स्वास्थ्य' राज्य सूची के अंतर्गत है।
 - स्वास्थ्य देखभाल नविश के लिये एक समर्पित वकिसात्मक वित्त संस्थान (DFI) की आवश्यकता है।

<i>Public Bill</i>	<i>Private Bill</i>
1. It is introduced in the Parliament by a minister.	1. It is introduced by any member of Parliament other than a minister.
2. It reflects of the policies of the government (ruling party).	2. It reflects the stand of opposition party on public matter.
3. It has greater chance to be approved by the Parliament.	3. It has lesser chance to be approved by the Parliament.
4. Its rejection by the House amounts to the exp-ression of want of parliamentary confidence in the government and may lead to its resignation.	4. Its rejection by the House has no implication on the parliamentary confidence in the government or its resignation.
5. Its introduction in the House requires seven days' notice.	5. Its introduction in the House requires one month's notice.
6. It is drafted by the concerned department in consultation with the law department.	6. Its drafting is the responsibility of the member concerned.

//

वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. एक नजि सदस्य का विधायक एक संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया विधायक होता है जो नस्वाचति नहीं होता बल्कि केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामति होता है ।
2. हाल ही में भारत की संसद ने अपने इतहास में पहली बार एक नजि सदस्य का विधायक पारति किया ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

- कानून बनाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में वधियक पेश करने के साथ शुरू होती है।
- वधियक को कोई मंत्री या मंत्री के अलावा कोई अन्य सदस्य भी पेश कर सकता है। पहले मामले में मंत्री द्वारा पेश किये गए वधियक को सरकारी वधियक कहा जाता है, जबकि अन्य सदस्यों द्वारा पेश किये गए वधियक को नज्जी वधियक के रूप में जाना जाता है।
- दूसरे शब्दों में एक नज्जी सदस्य का वधियक एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य (नरिवाचति या मनोनीत) द्वारा पेश किया जाता है। इसकी शुरुआत से पहले एक महीने की नोटिस अवधि आवश्यक है। मसौदा तैयार करना उस सदस्य की एकमात्र जम्मेदारी है जो वधियक पेश करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- संसद द्वारा पारति पहला नज्जी सदस्य वधियक मुस्लमि वक्फ वधियक, 1952 था, जिसका उद्देश्य वक्फों का बेहतर शासन और प्रशासन प्रदान करना था। इसे 1954 में पारति किया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- वर्ष 2015 में राज्यसभा द्वारा पारति ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार वधियक, 2014, पछिले 45 वर्षों में राज्यसभा की मंजूरी पाने वाला पहला नज्जी सदस्य बलि बन गया।

अतः वकिल्प D सही है।

प्रश्न. "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनविर्यता होने के अलावा प्राथमिकि स्वास्थ्य संरचना सतत् विकास के लिये एक आवश्यक पूरव शर्त है" वश्लेषण कीजिये। (2021)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/right-to-health-2>

